



'बजट में दिल्ली और बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है'

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् ने कहा, केन्द्रीय बजट का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना है

-रेपु मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूगो-
नई दिल्ली, 1 फरवरी। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केन्द्रीय बजट असल में दिल्ली के मतदाता को लुभाने की कोशिश है।

अगर आप 7 लाख रुपए से 12 लाख रु. सालाना कमा रहे हैं तो आप टैक्स रूपए के लाये में जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोग हैं जो हर माह 60 हजार से एक लाख रु. तक कमाते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था अखिल भारतीय स्तर पर सिर्फ 3.2 करोड़ लोगों को ही लाभ हो रहा है और दिल्ली में तो यह संभाला और पी कम है।

- चिदम्बरम् ने आरोप लगाया, बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, समाज कल्याण, कृषि क्षेत्र के बजट आठांठन में कटौती की गई है।
- चिदम्बरम् ने अनुसूचित जाति, जनजाति, ओडीसी तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के बजट में कटौती को कूर कदम बताया।
- उहोंने कहा, नई टैक्स प्रणाली में मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, खासकर, उहोंने जो हर माह 60,000 से एक लाख रुपए तक कमाते हैं, लैकिन पैट्रोल, डीजल में जीएसटी में कोई कटौती नहीं की गई है।
- उहोंने कहा, बेरोजगारी दूर करना सबसे अहम मांग है, पर, रोजगार सूजन की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया है।

मदद मिल सके। बेरोजगारी दूर करने पर भजट में बिहार का भी ध्यान रखा भी कुछ नहीं किया गया है जो कि गया है जहां अगले वर्ष आम चुनाव होने वाले हैं।

बजट का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतना ही ना कि देश की जनता के जीवन की उग्रता को सुधारना।

चिदम्बरम् ने कहा अपना आठांठ बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री नया विजन देने में पूरी तरह से असफल रही है, वे अवश्यक सुधार भी नहीं कर पाए। पर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, पूर्वोत्तर के विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट में कटौती की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य वर्गों के लिए विधानसभा विजन के लिए विधायिक आठांठ बजट से भी कटौती की गई है जो कूर कदम है।

बजट को रोटिंग देने के बारे में पूछा गया तो एक पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि दिल्ली व बिहार के मतदाता इसे हार्द रोटिंग देंगे पर शेष भारत के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती।

नाबालिंग से दुष्कर्म, आरोपी को आजीवन कारावास

जयपुर, 1 फरवरी। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर दिव्यने नाबालिंग कांजिंज छात्रों के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रोहित शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके हालत में 24 वर्षीय आरोपी युवक रोहित शर्मा भी लाख रुपए का 4.4 प्रतिशत रेलवे को दी गई, पर ऐसा नहीं हुआ।

रेलवे को 31,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण करना है और रेल दुर्घटना नियोगित तंत्र "कवच" भी स्थापित करना है, साथ ही मैक इन इंजियों को भी प्रोत्साहन देना है। यह सब बजट प्रस्तावों में परिलक्षित नहीं हो रहा है।

कॉर्डोस के निर्माण की योजनाओं या आँकड़े के स्वीकार किया था तथा जेर नये रेल मार्गों के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की अवश्यकता पर चुप्पी साध रखी है। जरूरत है। इसलिये, सीतारमण के बजट शुरुवात को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष में इसे बटाकर 4.4 प्रतिशत करने की अवश्यकता पर चुप्पी साध रखी है। जरूरत है। इसलिये, सीतारमण के बजट शुरुवात को पेश किये गये प्रस्ताव संतुलित प्रकृति के प्रतीत हुये हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक मातादीन शर्मा ने जीडीपी के 4.9 प्रतिशत के बजट घाटा (शेष अंतिम पृष्ठ पर) को देंगी।

कॉर्डोस के सेमी-हाई स्पीड तथा देते हुए कहा गया था कि इस वित्त वर्ष हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति भी हो तो भी यह अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि नाबालिंग की सहमति कानून में को

